

‘अमेरिका, उन देशों पर जो रूस से ऑयल खरीदना जारी रखेंगे, 500 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा’

अमेरिका के सिनेट में प्रस्तुत इस विधेयक, जिसे दोनों पार्टियों, रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी, का आंशिक समर्थन प्राप्त है, का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा

-सुकमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
वार्षिकस्टार/एड दिल्ली, 3 जुलाई। अमेरिकी सिनेट में पेश एक नया बिल (सेंटरिनग रिशिया एक्ट ऑफ 2025, एस.1241) यह जानता है कि जो ऑयल, जिनमें भारत भी शामिल है, से रूस से तेल, गैस, पेट्रोकमिकल तथा यूरोपियन की खरीद जारी रखेंगे, उनके उत्पादों पर अमेरिका 500 प्रतिशत टैरिफ (आरा शुल्क) लगा सकता है।

यह विधेयक सोन्टर लिंडेस ग्राहम और चिर्च ब्लूरो द्वारा देश पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। विधेयक सोन्टर के कारिगरमें पारित होने का समर्थन किया गया है और इसे 80 से अधिक सीरियों का समर्थन प्राप्त है। डॉनल्ड ट्रम्प ने न केवल इस विधेयक के कारिगरमें पारित होने का समर्थन किया गया है, बल्कि भविष्य के राष्ट्रपतियों को रखने पर दबाव बनाने के लिए एक “टूलबांस्ट” देने की वकालत की है, हालांकि उन्होंने इसमें एक प्रैज़िडेंशियल छूट का प्रावधान भी सुनिश्चित किया है, जिससे राष्ट्रपति चाहे तो टैरिफ को निर्लिपित कर सकते हैं।

- रूस ने प्रत्युत्तर में घोटाया है कि भारत जैसे देश पर इस तरह का दबाव बनाना, यूक्रेन में चल रहे शांति प्रयासों को जोखिम में डाल सकता है।
- भारत, अमेरिका का फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसज, ऑटो पार्ट्स तथा जावाहरात निर्यात करता है। भारत के ये निर्यात, अमेरिका में बिना किसी रुकावट के पहुंचते हैं। पर, अगर, अमेरिका ने भारत के इस निर्यात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो ये आइटम इतने महंगे हो जायेंगे कि अमेरिका में इनकी बढ़िया खत्म सी हो जायेगी।
- अमेरिका अपनी इकोनॉमिक ताकत का उपयोग, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए काम ले सकता है। अतः भारत ने अब ज्यादा से ज्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे वो अमेरिका की व्यवसायिक धमकी में भी जी सके तथा अमेरिका के समृद्ध मार्केट में दीर्घकालीन एन्ट्री बनाये रख सके।

क्रेमलिन ने घोटाकी दी है कि भारत जैसे प्रमुख खरीदारों पर दबाव

डालने जैसे कदम यूक्रेन में शांति प्रयासों को कमज़ोर कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानाना है कि यह 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव एक गंभीर खत्ता है। यह उन देशों को नियाना बनाता है, जो रूस से तेल खरीद जारी रखते हैं, लेकिन यह दंड सीधे उनके तेल व्यापार पर लागू नहीं होता।

भारत के संदर्भ में, यद्यपि वह अपनी कुल जस्तर के कच्चे तेल 40 प्रतिशत आयत रूस से करता है, लेकिन अमेरिका को वह तेल नियान नहीं करता, ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष टैरिफ लगाने का कोई रासायनिक व्यापक नहीं है।

भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया गया है इस विशेष सम्बन्ध के लिए आया के लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता को और गहरा करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों को अग्रे बढ़ाने की ओर नई विद्यमान लालता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद है कि आया की उक्ती ऐतिहासिक राजकीय आया दोनों देशों के संबंधों को नई गति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी को मिला धाना का सर्वोच्च सम्मान

अबकारा/नवीनीदिल्ली, 03 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धाना के सर्वोच्च सम्मान, ‘द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ चाना’ से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यस सम्मान प्रदान किया। मोदी ने बुधवार को इस सम्मान के लिए धाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे ‘अलंकृत गर्व का विषय’ बताया। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को ओर से पुरस्कार स्वीकार करते हुए इस सम्मान के लिए यहाँ आया।

भाजपा ने उन्हें यह सम्मान के लिए धाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे ‘अलंकृत गर्व का विषय’ बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नई धाना के लागू करने का जारी होना चाहिए।

भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया गया है इस विशेष सम्बन्ध के लिए आया के लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता को और गहरा करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों में अमेरिका को किये जाने वाले नियान तहत करता है।

इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, बस्ट, आईटी सेवाएं, ऑटो पार्ट्स और रस्ल-आधुनिक शामिल हैं, जो फिलहाल अमेरिका में न्यूत्राम व्यापार बढ़ावा देते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में मतदाता के धार्मिक ध्वनीकरण की राजनीति शुरू हो गई?

भाजपा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर “नमाजवादी” होने का व्यंग्य दागा तथा विपक्ष ने भाजपा पर एनआरसी (नैशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स) को पीछे के दरवाजे से लाकर लागू करने का आरोप लगाया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 3, जुलाई। चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार में मतदाताओं का धार्मिक आयाग पर ध्वनीकरण शुरू हो गया है। जहाँ भाजपा ने राजद (राष्ट्रीय जनता दल) नेता तेजस्वी यादव पर “नमाजवादी” तंज करते हुए इसकी शुरूआत की, वहाँ विपक्षी नेताओं ने एनडीए पर एनआरसी को दरवाजे से लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

तेजस्वी यादव द्वारा यह कहे जाने पर किंवदं एक एक्ट को करवे में फैक्ट दिया जाएगा और बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता संवित यादव पर “महागठबंधन के लिए आया” तेजस्वी यादव करने की मांस्त्री रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद है कि आया की नीति “सभी जातियों और समुदायों के लिएकाम” करने की रही है।

इसकी बाँध, चुनाव आयोग द्वारा नियर्य को लेकर एक बड़ा विवाद विहार की मतदाता सूचियों से विषेष उभरता दिख रहा है। इस प्रक्रिया के गहराना उपरान्त नेताओं में रिपब्लिकन राजनीतिक सदन ने नियर्य लिया कि उनका एक अलाज द्वारा मनोनीत एक नेता ही चुनाव आयुर्त से मिल सकेगा।

- तेजस्वी यादव का दावा है कि वक्त एक्ट को कुड़ी की टोकरी में फैक्ट दिया जायेगा तथा बिहार में कभी लागू नहीं होगा, पर, संवित यादव ने कहा कि महागठबंधन बिहार में “शरिया कानून” लागू करना चाहता है।
- प.बंगल की मु.मंत्री ने कहा कि बिहार में स्पैशल इन्वैन्सिव रिवीजन (एसआईआर) को लागू करने का असली टारगेट तो प.बंगल है। बंगल के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को नाम प्रिटा दिए जाएंगे तथा उनकी जगह, बिहार, यू.पी., राजस्थान, हरियाणा आदि के मतदाताओं से भर दी जायेगी।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मु.मंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में बिहार में एनआरसी लागू करने के बारे में कहा था, “कहाँ का एनआरसी। बिल्कुल लागू नहीं होगा।” देखना है, अब उनका रुख क्या रहता है।

इसकी बाँध, चुनाव आयोग द्वारा नियर्य को लेकर एक बड़ा विवाद विहार की मतदाता सूचियों से विषेष उभरता दिख रहा है। इस प्रक्रिया के गहराना उपरान्त नेताओं में रिपब्लिकन राजनीतिक सदन ने नियर्य लिया कि उनका एक अलाज द्वारा मनोनीत एक नेता ही चुनाव आयुर्त से मिल सकेगा।

की तुलना “वोटबंदी” से की, यह कहते हुए कि बिहार के प्रवाली मजदूर चुनाव आयोग द्वारा तथ्य की ओर महाने की सम्पर्कीयों से लोकाव नामकन नहीं करवा रहा। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के अवधारणीय क्षेत्रों के लिए चुनाव चुनाव आयोग के बारे में विषेष उभरता दिख रहा है। इसकी बाँध, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एस.आई.आर. की आवश्यकता को उत्तरांत द्वारा तोड़ा है। एक बड़ा विवाद विहार की ओर आयोग के अधिकारियों ने एस.आई.आर. की आवश्यकता को उत्तरांत द्वारा तोड़ा है।

सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को सुनी, लेकिन उत्तरांत द्वारा तोड़ा है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए चुनाव चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में भाग नहीं ले पाये और तीन घंटे बाहर ही बैठे रहे।

क्योंकि, अचानक निर्वाचन सदन ने नियर्य लिया कि केवल पार्टी द्वारा मनोनीत एक

